मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

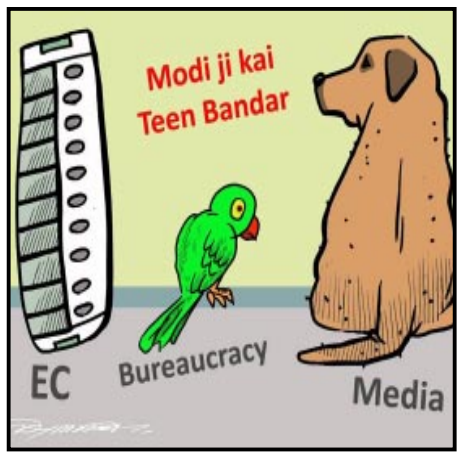

बदमाश उम्मीदवार अरविन्द शर्मा	3
कितने सन्तों की जान भाजपा लेगी	4
संदेहों के घेरे में सीजेआई कमेटी	5
प्रज्ञा ठाकुर के वाहियात बयान	6
बार बालाओं को नचाकर भीड़	8

वर्ष 32 | अंक -25 | फ़रीदाबाद | 5-11 मई 2019 | फोन - 9999595632 | 2.50 ₹

कृष्णपाल गुर्जर ने आरडब्ल्यूए को सौंपी वोट की ठेकेदारी

रिहायशी इलाकों से चंदा लूटने वाली एसोसिएशनों को मिला मोटा फंड

सेक्टर 37 में आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी बच्चों के साथ भाजपा का प्रचार करते हुए।

सेक्टर 15 आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के साथ भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगते मंत्री विपुल गोयल। बैठक से सेक्टर 15 के निवासी गायब थे।

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद: यहां की लोकसभा सीट से सांपनाथ और नागनाथ (कृष्णपाल गुर्जर-अवतार सिंह भड़ाना) के चुनाव प्रचार में दोनों के कार्यकर्ता घटिया स्तर पर उतर आये हैं। तरह-तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

आरडब्ल्यूए ले रही है ठेकेदारी

गूर्जरों के गांवों में भारी विरोध का सामना कर रहे कृष्णपाल गुर्जर ने अब अपना ध्यान शहरी मतदाताओं पर केंद्रित कर दिया है। इसका ठेका हर सेक्टर में भाजपा ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को सौंप दिया है। आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी अचानक सारे सारे सेक्टर के वोटों के ठेकेदार बन बैठे हैं। आरडब्ल्यूए जहां चंदा उगाही का सबसे बड़ा सेंटर हैं, वहीं अब वो राजनीति में भी दिलचस्पी ले रही हैं।

सेक्टर 28, 29 और 19 का उदाहरण पेश है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उनका बेटा देवेंद्र चौधरी जो सीनियर डिप्टी मेयर भी है, वह भी उनके साथ सेक्टर 28 में ही रहता है। बाकी सेक्टरों के मुकाबले सेक्टर 28, 29, 19 में नगर निगम ने सबसे ज्यादा काम दोनों को खुश कराने के लिए कराये। सेक्टर 28, 29, 19 में बहुत सारे पॉकेट्स हैं जिनमें ए, बी, सी, में अलग-अलग आरडब्ल्यूए बनी हुई हैं। करीब-करीब सभी पर भाजपा और आरएसएस का कब्जा है।

इतना सबकुछ होने के बावजूद पता नहीं कृष्णपाल गुर्जर और उनके चमचों को लग रहा है कि सेक्टर के लोग कृष्णपाल गुर्जर को वोट नहीं करेंगे। इसलिए इन लोगों ने योजना बनाई कि क्यों न घर-घर जाकर गुर्जर के लिए वोट मांगे जायें। यहां पर एक एसोसिएशन का उदाहरण देना काफी होगा।

इसी बुधवार वाले दिन सुबह-सुबह आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी चारों तरफ फैल गए और वहां पार्क में व अन्य स्थानों पर जमें लोगों से कहने लगे कि हम लोग शाम को वोट मांगने आयेंगे, कृष्णपाल के लोग भी होंगे। इन पदाधिकारियों के साथ-साथ कुछ दिहाड़ी मजदूर थे जो हर घर पर आग्रहपूर्वक झंडा लगा रहे थे। जिन लोगों ने झंडे लगवाने से मना किया, आरडब्ल्यूए के चश्मे वाले पदाधिकारी ने फोन करके कहीं सूचना भी दी कि कुछ लोग मना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने न चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए झंडे ले लिये।

बुधवार शाम का नजारा बिल्कुल अलग था। शाम को सेक्टर पार्क में सारे आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी, आरएसएस के कार्यकर्ता और कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक भगवा टोपी लगाकर खड़े हो गए। उन्होंने पॉकेट बी के लोगों से आह्वान किया कि वह हमारे दल में शामिल होकर घर-घर वोट मांगने के लिए चले आयें। कुछ देर इंतजार के बाद जब घरों से लोग पार्क में नहीं पहुंचे तो सारे आरडब्ल्यूए पदाधिकारी, आरएसएस कार्यकर्ता और गुर्जर समर्थक घरों की तरफ बढ़े। वे लोग भाजपा की एक टोपी और कमल के निशान वाला कपड़े पर लगाने के लिए बिल्ला बांटने लगे। यह लोग हर घर पर पहुंचे और उस घर के मालिक से पड़ोस वाले घर तक चलने के लिए कहते रहे लेकिन किसी ने भी उनके साथ जाने से सहमति नहीं जताई। इससे इन लोगों को खासी मायूसी हासिल हुई।

इस संबंध में सेक्टर 28 के लोगों से जब पूछा गया कि ऐसी बेरुखी वे लोग क्यों दिखा रहे हैं, उनका कहना था कि कृष्णपाल गुर्जर ने आरडब्ल्यूए वालों को फंड दिए हैं। इनके पदाधिकारियों ने हर घर से वोट दिलाने का वादा किया है। लेकिन वोट एक निजी मामला है। आरडब्ल्यूए के लोग हमसे चंदा ले जाते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। जो काम नगर निगम करता है, उसका श्रेय जबरन खुद और कृष्णपाल गुर्जर को दे देते हैं। हर बार नई एसोसिएशन खड़ी हो जाती है और ये लोग किसी भी साल लिये गए चंदे का हिसाब तक नहीं देते हैं। आरडब्ल्यूए चंद लोगों के खाने-कमाने का धंधा बन गया है।

इनमें से कुछ बिजनेसमैन बने फिरते हैं, लेकिन बिजनेस फेल हो गया है तो आरडब्ल्यूए को कमाई का जरिया बना लिया गया है। कबाड़ियों को ठेका देने के नाम पर मोटी वसूली की जाती है। बाहर से माल बेचने आने वालों को सुरक्षा के नाम पर रोका जाता है और बाद में कुछ पैसे लेकर अंदर आने की परमिट सभी गेटों पर तैनात गार्ड के जरिये दी जाती है। जाड़े के दिनों में कश्मीर से शाल बेचने आए गरीबों से इसी तरह की वसूली की गई थी। जिन कश्मीरियों ने पैसे नहीं दिये, उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया।

सेक्टर 29 की सड़क साफ करने वाले सफाई कर्मचारी एक आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिये काम करते हैं। भाजपा के लोगों ने उनको भी अपनी कूड़ा गाड़ी पर भाजपा का झंडा देकर उसे लगाने को कहा गया। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इस बारे में मजदूर मोर्चा ने उनसे बात की आखिर उन्होंने भाजपाई झंडा लेने से क्यों इनकार कर दिया, एक सफाई कर्मचारी ने जवाब दिया कि इस झंडे के लगाने से हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली।

अलबत्ता लोगों को एक संदेश जायेगा कि सफाई कर्मचारी भी भाजपा समर्थक हो रहे हैं। इनको फायदा होगा। हमें क्या मिलेगा। इसलिए हम ऐसा संदेश क्यों दें। जब उस कर्मचारी को बताया गया कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इलाहाबाद में सफाई कर्मचारियों के पैर धुले हैं, उसने कहा कि हम कच्चे कर्मचारी हैं। कभी हम निगम के कर्मचारी होते थे। अब यह काम प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है, जो हमारा शोषण करती है। मोदी दी चाहे जितना पैर धो लें लेकिन वे देश के तमाम नगर निगमों में हुई इस चालबाजी को नहीं बदल सकते। अगर उनमें हिम्मत है तो देश के सभी नगर निगमों में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का कर दें। इसलिए यह पैर धोने का नाटक है। हमारे पेट में रोटी न हो और आप हमारा पैर लक्स साबुन से धुलें तो उससे हमारा पेट तो भरने से ही रहा।

नागनाथ भी कम नहीं

कांग्रेस प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना का चुनाव प्रचार अभी ठीक से उठ नहीं पाया है। लेकिन ओछी हरकतों का दौर वहां से भी जारी है। हाल ही में अवतार का एक विडियो वायरल करने की कोशिश की गई। जिसमें वह कृष्णपाल गुर्जर और उनके मामा पर एक-दो करोड़ लेकर हत्या कराने का आरोप लगा रहा है। आरोप में कितनी सत्यता है, यह कोई नहीं जानता लेकिन इसे सनसनीखेज बनाने की कोशिश जरूर की गई। यह सही है कि कृष्णपाल और उसका मामा तमाम अनैतिक गतिविधियों के लिए बदनाम हैं, जिसमें पुलिस वालों का तबादला कराने के नाम पर वसूली, जमीनों पर कब्जे का धंधा, बड़े-बड़े मॉल या दुकानों में हिस्सेदारी जैसे आरोप लगते रहे हैं। केंद्र में मंत्री बनने के बाद फरीदाबाद में खड़ी की गई अकूत संपत्ति का आरोप भी है लेकिन पैसे लेकर हत्या कराने का आरोप पहली बार विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी ने लगाया है। इस वायरल वीडियो को लेकर अभी तक कृष्णपाल गुर्जर की ओर से पुलिस में न तो कोई शिकायत की गई है और न ही जांच की मांग की गई है।

अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद से तीन बार सांसद रहा है। उसके बारे में फरीदाबाद का हर मतदाता जानता है। यही वजह है कि फरीदाबाद का मतदाता एकदम से चुप हो गया है। उसे दो अनचाहे लोगों में किसी एक को कड़वा घूंट पीते हुए चुनना है। बाकी प्रत्याशियों में इतना दमखम नहीं है। आम आदमी पार्टी एक नाकाम लहर खड़ी करने की कोशिश कर रही है लेकिन वह मुख्य रेस में अभी तक शामिल नहीं हो पाई है। उसका प्रत्याशी पंडित नवीन जयहिंद शिवभक्त कावंड़ियां तो प्रचार में कृष्णपाल और अवतार से भी ओछी हरकतें कर रहा है। शक्ल तो सड़क छाप बना ही रखी है।

चार लाख करोड़ का मोदी कोयला घोटाला

गिरीश मालवीय

वो लोग आज जरा सामने आएं जो कहते हैं कि मोदी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ ..... 4 लाख करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है

जी हां 'पूरे 4 लाख करोड़ का घोटाला' लेकिन बिका हुआ मीडिया इस खबर को पूरी तरह से हजम कर गया है..... यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पुहंचा है.....

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में कहा गया है कि सरकार ने देशभर में कच्चे लोहे की 358 खदानों की लीज का एक्सटेंशन बिना वैल्यूएशन किए कर दिया है। इससे सरकार को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

यदि यही भाजपा बात बात में यूपीए की सरकार में 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में 2.76 लाख करोड़ रुपए के नुकसान को घोटाला कहती है तो यह भी उसी तरह का घोटाला है.....

सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह बात वही वकील कह रहा है जो सबसे पहले कोल गेट घोटाले को सामने लाया था यह याचिका उसी वकील एलएम शर्मा ने दाखिल की है.....

एमएल शर्मा वही वकील हैं, जिन्होंने कोयला घोटाले का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़कर यूपीए सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर दी थी. कैग रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ही कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द करने की मांग की थी. जिसके बाद कई ब्लॉकों का आवंटन रद्द हुआ था. .....राफेल का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचाने वाले पहले वकील भी एमएल शर्मा ही हैं। पनामा पेपर्स लीक का मामला भी एमएल शर्मा ही सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और आरबीआई से जवाब मांगा था.....ओर भी ऐसे बहुत से केस हैं.....

आज यह वकील अपनी याचिका में कोर्ट को बता रहा है कि देशभर में कच्चे लोहे व खनिज की माइनिंग खदानों की लीज का एक्सटेंशन करने का फैसला लेकर केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार किया है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि 358 खदानों की माइनिंग लीज की अवधि को बढ़ाने का फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार ने न तो उनका वर्तमान समय के अनुसार वैल्यूएशन कराया और न ही उनकी नीलामी की प्रक्रिया की..... केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर जिसके पास पहले से माइनिंग लीज थी, उसे दोबारा वही खदान की माइनिंग लीज दे दी..... इस तरह से लोगों के टैक्स से अर्जित करीब 4 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान सरकार को हुआ.....

याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में संशोधित माइन्स एंड मिनरल्स एक्ट लाकर राज्य सरकारों को बाध्य किया कि वह 288 कच्चे लोहे के मिनरल ब्लॉक्स की खदानों की लीज की अवधि को बढ़ा दें..... याचिकाकर्ता का आरोप है कि ऐसा केंद्र सरकार ने इसलिए किया क्योंकि इसकी एवज में उनकी पार्टी

को भारी रकम चंदे के रूप में दी गई थी.....

याचिकाकर्ता के अनुसार केंद्र के दबाव में गोआ ने 160, कर्नाटक ने 45 और उड़ीसा ने 31 खदानों की लीज की अवधि को बढ़ा दिया। इनमें से ज्यादातर खदानों पर वेदांता ग्रुप और टाटा ग्रुप का नियंत्रण है। ये दोनों ही ग्रुप सत्तारूढ़ दल को भारी चंदा देते रहे हैं.....

इस मामले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए बोबड़े की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया हैं और पूछा है कि इन सारी माइनिंग लीज को क्यों न रद्द किया जाए? .....कोर्ट ने उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है.....

अफसोस की बात तो यह भी है कि इतना स्पष्ट भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बावजूद कांग्रेस समेत सारी विपक्षी पार्टियां मौन धारण किये हुए हैं.....